आकाशवाणी
क्षेत्रीय समाचार एकांश
देहरादून (उत्तराखण्ड)
बृहस्पतिवार 18.12.2025
समय 07.20

मुख्य समाचार :–

- प्रदेश में 'जन–जन की सरकार, जन–जन के द्वार' अभियान की शुरुआत। अभियान के तहत जरूरतमंदों को मौके पर ही विभिन्न योजनाओं का लाभ प्रदान किया जा रहा है।
- कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा– विकसित भारत– जी–राम–जी विधेयक गांवों के विकास को सुनिश्चित करेगा।
- खेल मंत्री रेखा आर्या ने अल्मोड़ा के सोमेश्वर विधानसभा क्षेत्र के रैत में बहुप्रतीक्षित मिनी स्टेडियम का शिलान्यास किया।
- आईआईटी रुड़की में जैव प्रौद्योगिकी पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन संपन्न।

''जन–जन की सरकार, जन–जन के द्वार''

प्रदेश सरकार का 'जन–जन की सरकार, जन–जन के द्वार' अभियान कल से शुरू हो गया है। अभियान के तहत न्याय पंचायत स्तर पर शिविर आयोजित कर आम लोगों को सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जा रही है और जरूरतमंदों को मौके पर ही विभिन्न योजनाओं का लाभ प्रदान किया जा रहा है। यह महत्वाकांक्षी अभियान 45 दिनों तक संचालित किया जाएगा। अभियान में राजस्व, ग्राम्य विकास, पंचायती राज, कृषि, समाज कल्याण सहित 23 विभाग शामिल हैं।

अभियान के पहले दिन राज्य के सभी जिलों में निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार चयनित न्याय पंचायतों में शिविर आयोजित किए गए, जिनमें बड़ी संख्या में लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इसी क्रम में कुमाऊं मंडल के आयुक्त दीपक रावत ने पिथौरागढ़ जिले के न्याय पंचायत दौला में अभियान का शुभारंभ किया। इस अवसर पर आयोजित शिविर में 800 से अधिक लाभार्थियों ने प्रतिभाग कर सरकारी योजनाओं की जानकारी प्राप्त की।

चम्पावत जिले के सिमल्टा में आयोजित शिविर में 500 से अधिक लोग लाभान्वित हुए। वहीं अल्मोड़ा और बागेश्वर में भी शिविरों का आयोजन किया गया। इसी तरह ऊधम सिंह नगर जिले में मुख्य विकास अधिकारी दिवेश शाशनी की अध्यक्षता में खटीमा में आयोजित शिविर में 73 शिकायतें दर्ज की गईं, जिनमें से 38 मामलों का मौके पर ही निस्तारण किया गया।

उधर, देहरादून जिले की सुदूरवर्ती न्याय पंचायत क्वांसी और उत्तरकाशी जिले की न्याय पंचायत नानई से भी अभियान का शुभारंभ किया गया।

जी–राम–जी

लोकसभा ने विकसित भारत– रोज़गार और आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण), विकसित भारत –जी राम जी विधेयक 2025 पर चर्चा शुरू हो गयी है। यह कानून बीस साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम की जगह लेगा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि यह विधेयक गांवों के विकास को सुनिश्चित करेगा।

विकसित भारत– जी–राम–जी विधेयक का पूरे उत्तराखंड में व्यापक स्वागत हो रहा है। नए विधेयक के तहत अब प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में भी 125 दिनों का रोज़गार उपलब्ध कराया जाएगा। उधमसिंह नगर से जिला विकास अधिकारी सुशील मोहन डोभाल ने बताया कि यह भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जो ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को रोज़गार उपलब्ध कराने में अहम भूमिका निभा रही है।

वहीं ग्राम भमरौला के ग्राम प्रधान जियाउल रहमान का कहना है कि केंद्र सरकार की इस पहल से ग्रामीण क्षेत्रों में रोज़गार के अवसर बढ़ेंगे।

लाभार्थियों का कहना है कि 125 दिनों का रोज़गार मिलने से उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी।

खेल मंत्री

खेल मंत्री रेखा आर्या ने अल्मोड़ा के सोमेश्वर विधानसभा क्षेत्र के रैत में बहुप्रतीक्षित मिनी स्टेडियम का शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यह स्टेडियम क्षेत्र के युवाओं को नई ऊर्जा और दिशा प्रदान करेगा।

अपने संबोधन में खेल मंत्री ने कहा कि सरकार का संकल्प है कि प्रदेश के हर कोने तक खेल सुविधाएँ पहुँचें और हर घर से एक खिलाड़ी तैयार हो– यही 'खेलों वाला उत्तराखंड' का सपना है।

खेल मंत्री ने कहा कि जहां पिछली सरकारों ने केवल औपचारिकताएँ निभाईं, वहीं वर्तमान सरकार ने इस सपने को हकीकत में बदलने का काम किया है।

"मानक मंथन"

भारतीय मानक ब्यूरो की देहरादून शाखा द्वारा देहरादून में "मानक मंथन–कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व आवश्यकताएँ" विषय पर एक महत्वपूर्ण विचार–विमर्श कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए धर्मपुर विधायक विनोद चमोली ने कहा कि सीएसआर सतत विकास, सामाजिक उत्तरदायित्व और उद्योग व समाज के बीच समन्वय का एक महत्वपूर्ण माध्यम है।

वहीं बीआईएस के देहरादून कार्यालय के निदेशक सौरभ तिवारी ने बताया कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य उद्योगों और अन्य हितधारकों को कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व से जुड़े भारतीय मानकों की आवश्यकताओं से अवगत कराना था।

आईसीएबीएसबी का समापन

रुड़की स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान– आईआईटी में जैव प्रौद्योगिकी और संरचनात्मक जीवविज्ञान में प्रगति विषय पर एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। चार दिवसीय यह वैश्विक वैज्ञानिक सम्मेलन बायोटेक रिसर्च सोसाइटी ऑफ इंडिया के सहयोग से आयोजित किया गया, जिसमें 40 से अधिक देशों से आए 700 से अधिक प्रतिनिधियों और लगभग 200 आमंत्रित वक्ताओं ने भाग लिया।

सम्मेलन के संयोजक प्रोफेसर प्रविंद्र कुमार ने कहा कि विकसित सहयोग और निष्कर्ष उच्च–प्रभावी अनुसंधान को आगे बढ़ाने के साथ ही आईआईटी रुड़की की वैश्विक वैज्ञानिक सहभागिता को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

आग

चमोली जिले में भारत–चीन सीमा पर स्थित नीति–मलारी घाटी के मेहरगांव में कल रात अज्ञात कारणों से भीषण आग लग गई। आग की चपेट में आने से कई आवासीय घर जलकर खाक हो गए।

गौरतलब है कि सर्दियों के दौरान स्थानीय ग्रामीण शीतकालीन प्रवास के चलते निचले इलाकों में चले जाते हैं। गांव में कोई भी व्यक्ति निवासरत न होने के कारण किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई, जिससे एक बड़ी अनहोनी टल गई।

अस्पताल का उच्चीकरण

ऊधम सिंह नगर जिले में स्वास्थ्य सेवाओं को और सुदृढ़ करते हुए राज्य सरकार ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र शक्तिफार्म को उच्चीकृत कर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बना दिया है। इस संबंध में शासन स्तर से शासनादेश जारी कर दिया गया है।

स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने बताया कि 30 शैय्या युक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आईपीएचएस मानकों के अनुरूप विशेषज्ञ चिकित्सकों, सामान्य चिकित्सकों, नर्सिंग स्टाफ, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन सहित अन्य मेडिकल स्टाफ की तैनाती की जाएगी।

एमओयू साइन

हरिद्वार जिला कारागार में बंद कैदी अब उच्च शिक्षा का लाभ ले सकेंगे। प्रदेश में दूरस्थ शिक्षा के विस्तार की दिशा में उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय ने जिला कारागार हरिद्वार के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। एमओयू के तहत विभिन्न अपराधों में निरुद्ध कैदियों को विश्वविद्यालय द्वारा संचालित दूरस्थ शिक्षा पाठ्यक्रमों में अध्ययन का अवसर प्रदान किया जाएगा। इसके साथ ही भविष्य में प्रदेश के अन्य जिलों की जेलों में भी इस प्रकार की पहल की जाएगी।

उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर नवीन चंद्र लोहनी ने कहा कि उच्च शिक्षा प्राप्त करना प्रत्येक नागरिक का अधिकार है, और इसे सुनिश्चित करने के लिए विश्वविद्यालय निरंतर प्रयासरत है।

एक नजर आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों पर...

दून–दिल्ली एक्सप्रेसवे 10–15 दिनों में जनता के लिए खोल दिया जाएगा, इस समाचार को दैनिक जागरण और अमर उजाला ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण ने सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के हवाले से लिखा है इसके चालू होने से दोनों शहरों के बीच यात्रा का समय साढ़े छह घंटे से घटकर दो घंटे हो जाएगा।

यूसीसी संशोधन विधेयक को राज्यपाल ने लौटाया इस समाचार को दैनिक जागरण ने पहले पृष्ठ पर स्थान दिया है।

उत्तराखंड में प्रवक्ता भर्ती आरक्षण के फेर में फंसी, इस समाचार को हिन्दुस्तान ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है।

दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण की खबर को सभी समाचार पत्रों ने प्रमुखता से पहले पृष्ठ पर प्रकासित किया है। नवोदय टाइम्स लिखता है– बीएस–4 से कम मानक वाले वाहन नहीं चलेंगे। अमर उजाला सुप्रीम कोर्ट के हवाले से लिखता है– दिल्ली–एनसीआर में प्रदूषण नियंत्रण के उपाय नाकाम, 9 टोल प्लाजा हटाएं या बंद करें।